International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 04(II), October - December, 2021, pp.111-118

कैशलेस भारतीय अर्थव्यवस्था और डिजिटलाइजेशन

श्री सत्यनारायण खींची*

सार

वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व एक कठिन दौर से गुजर रहा है और विश्व के अनेक देश इस समय कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रहे हैं। कैशलेस अर्थव्यवस्था में स्वीडन और कनाड़ा दोनों ही अग्रणी देश हैं। कैशलेस अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जिसके अन्तर्गत लेनदेन में कम से कम नकदी का प्रयोग होता है। कैशलेस अर्थव्यवस्था में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट–बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट या डिजिटल मोड द्वारा लेन–देन किया जाता है। भारत एक विकासशील देश है। नकदी रहित भारत की शुरूआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इनके द्वारा भारत को ''कैशलेस इंडिया डिजिटल इंडिया'' बनाने की दिशा में यह पहला कदम था। 8 नवम्बर 2016 की रात प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 500 और 1000 रूपये के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। नोटबंदी की घोषणा के बाद की पहली तिमाही में जीडीपी व वृद्धि दर घटकर 6.1 फीसदी पर आ गई थी। भारत प्रमुख रूप से नकदी संचालित अर्थव्यवस्था है, यहां कैशलेस लेन–देन की बजाय नकद द्वारा लेन–देन ज्यादा पसंद करते है। नोट बंदी के परिणामस्वरूप भारत में कैशलेस लेन–देन को बढ़ावा मिला। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने ऑनलाईन लेन–देन और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। इसके तहत लोगों की पुरस्कार भी दिए गए । भारत में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, भीम एप, फोन–पे, पेटीएम, एईपीएस, नेट–बैंकिंग, मोबाईल वॉलेट, इत्यादि के द्वारा नकदी रहित भारत (कैशलेस इंडिया) के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तीव्र प्रगति दर्ज की गई। कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटलीकरण अति आवश्यक है। इसमें विभिन्न चुनौतियां हैं जैसे– लेन–देन का खराब सुरक्षा तंत्र, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, नेट वर्क कनेक्टिविटी, अशिक्षित आबादी इत्यादि। एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल पे, पेटीएम, फोन–पे, और भीम एप जैसे दूसरे यूपीआई प्लेटफॉर्म पर माह करीब 1.22 बिलियन यानी करीब 122 करोड़ तक का लेन–देन होने लगा है। वहीं अगर वर्ष 2016 यानी 5 साल पहले की स्थिति की तुलना करें तो अब इसमें 550 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। 2016–17 में 1004 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन किए गए हैं। ये आँकड़ा 2020–2021 में 5554 करोड़ तक पहुँच गया। अप्रैल–मई 2021 में डिजिटल ट्रांजेक्शन 2020 की तुलना में सौ फीसदी अधिक हुआ है। डिजिटल पेमेन्ट इस कोरोना काल में देश के विकास के लिए वरदान साबित हुआ है।

शब्दकोशः *कैशलेस अर्थव्यवस्था, डिजिटल, जीडीपी, नेट–बैंकिंग, मोबाईल वॉलेट।*

प्रस्तावना

भारतीयों की नकदी पर निर्भरता दूसरे देश के लोगों से कहीं ज्यादा है। भारत में वर्ष 2016 के अनुसार लगभग 85 प्रतिशत लोग लेन–देन नकद करते थे जिसका जीडीपी में 67 प्रतिशत एवं श्रम बाजार में 85 से 90 प्रतिशत योगदान था। भारतीय जीडीपी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का योगदान लगभग 37 प्रतिशत है। जबकि भारत की आधी से ज्यादा आबादी गाँवों में रहती है। इतना ही नही लगभग 85 प्रतिशत लोगों की मजदूरी नकद रूप में मिलती है। इस बात से यह साबित होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था नकदी पर किस प्रकार निर्भर है?

[6] सहायक आचार्य (ई.ए.एफ.एम), राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक, राजस्थान।

नकदी रहित भारत की शुरूआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। 08 नवम्बर 2016 की रात से भारत में 500 और 1000 रूपये के नोटों को बंद कर दिया गया। यह कदम नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार का पहला कदम था। दरअसल यह आवश्यक भी था क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा नकदी संचालन हो रहा था। वर्ष 2014 में यह जीडीपी का 12.42 प्रतिशत था जबकि चीन और ब्राजील में 9.47 प्रतिशत तथा 04 प्रतिशत ही था। नकद संचालन में भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों का सालाना खर्च 21,000 करोड़ रूपए आता था। कैशलेस अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह नही के बराबर हो जाए तथा सभी लेन–देन डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service - IMPS), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (National Electronic Funds Transfer-NEFT) और रीयल टाइम ग्रास सेटलमेंट (Real Time Gross Settlement-RTGS) जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों एवं एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payment Interface - UPI) जैसे भुगतान माध्यमों से होने लगे हैं। वित्तीय वर्ष 2021 में भारत में डिजिटल भुगतान 53 अरब भारतीय रूपये तक पहुंच गया है। यह वित्तीय वर्ष 2018 में 20.7 अरब भारतीय रूपये से उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। कैशलेस भुगतान के विकल्पों में से भारत इंटरफेस फॉर मनी (Bharat Interface for Money - BHIM) ने 2018 के डेबिट कार्ड से भुगतान को पीछे छोड़ दिया। भीम लेनदेन का मूल्य 2018 से 2021 के बीच काफी बढ़ गया है, जबकि डेबिट कार्ड से भुगतान 2019 से स्थिर स्तर पर है, तो यह मान लिया जाये कि यह स्थिति कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है।

कैशलेस लेनदेन के प्रकारः

- **मोबाइल वॉलेट**

मोबाइल वॉलेट स्मार्टफोन में मौजूद एक वर्चुअल वॉलेट (आभासी वॉलेट) है, जिसमें पैसे डिजिटल मनी के रूप में रखे जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह एक डिजिटल पर्स है, जिसमें से पैसों को निकालकर लेन–देन और भुगतान किया जा सकता है।

- **प्लास्टिक मनी**

प्लास्टिक मनी का तात्पर्य प्लास्टिक से बने उन कार्ड्स से है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि से है जिनका इस्तेमाल निकासी एवं भुगतान आदि के लिये किया जा सकता है। प्लास्टिक मनी के प्रयोग से कैशलेस अर्थव्यवस्था को तो बल मिलता ही है साथ में नकदी लेकर चलने की झंझटों से भी मुक्ति मिल जाती है।

- **नेट बैंकिंग**

किसी भी बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का कम्प्यूटर, मोबाइल या किसी अन्य यंत्र के माध्यम से इंटरनेट के जरिये प्रयोग करना नेट बैंकिंग कहलाता है।

इसके लिये बैंक वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाकर उसे अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं।

तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (National Electronic Funds Transfer-NEFT) और रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (Real Time Gross Settlement-RTGS) नेट बैंकिंग के तहत आने वाली भुगतान प्रणालियाँ हैं।

- **यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस**

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payment Interface - UPI), राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payment Corporation of India) द्वारा आरम्भ की गई लेन–देन की एक नई प्रणाली है जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (Virtual Payment Address- VPA) का उपयोग कर धन का त्वरित हस्तांतरण सुनिश्चित करती है।

यह भुगतान का एक ऐसा माध्यम है जो सातों दिन चौबीसों घंटे कार्य करता है। इससे धन के लेन–देन में नकदी का चलन कम हो जाएगा तथा व्यापारिक भुगतान सरल सुरक्षित एवं पारदर्शी हो जाएगा।

- **पेमेंट बैंक**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दो प्रकार के लाइसेंस जारी किये जाते हैं, सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस (Universal Bank Licence) और विभेदित बैंक लाइसेंस (Differentiated Bank Licence)

एक पेमेंट बैंक, विभेदित बैंक लाइसेंस प्राप्त बैंकों की श्रेणी में आता है। पेमेंट बैंक एक विशेष प्रकार के बैंक हैं, जिन्हे कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलापों की अनुमति है।

इन बैंकों का उद्देश्य प्रवासी श्रमिक वर्ग, निम्न आय अर्जित करने वाले परिवारों, लघु कारोबारों, असंगठित क्षैत्र की अन्य संस्थाओं को सेवा प्रदान कर अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन का बढ़ावा देना है।

इस शोध का उद्देश्य

- भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था के प्रसार के बारे में अध्ययन करने के लिए।
- भारत में कैशलेस लेन–देन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए।
- भारत के आर्थिक व सामाजिक विकास में कैश लेन–देन की चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए।
- भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था के लागत–लाभ, विश्लेषण का मूल्यांकन करना।

क्रियाविधि (Methodology)

- इस शोध का अध्ययन पूर्ण रूप से वर्णनात्मक प्रकृति का है एवं द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। डेटा प्रामाणिक और विश्वसनीय स्त्रोत, लेख, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्र–पत्रिकाओं तथा मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गये हैं।

कैशलेस (डिजिटल) भुगतान से सरकार और जनता को लाभ

- **टैक्स चोरी पर रोक**

यदि अर्थव्यवस्था कैशलेस होती है तो टैक्स चोरी की घटनाओं में उल्लेखनीय रूप से कमी आएगी। ऐसा इसलिये क्योंकि प्रत्येक कैशलेस लेन–देन के प्रमाण डेटाबेस में अंकित हो जाते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति की वास्तविक आय से सम्बन्धित आँकड़े जुटाने में आसानी होती है।

- **काले धन पर रोक**

कैशलेस समाज का एक मुख्य लाभ यह है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिये किया गया आर्थिक लेन–देन ब्लैक मनी के बाजार को खत्म कर सकता है।

नकदी आधारित अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी इकट्ठा करना, नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, आतंकवाद, जबरन वसूली, डकैती आदि जैसे आपराधिक गातिविधियों को अंजाम देना आसान बन जाता है। कैशलेस अर्थव्यवस्था इनसे मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होगी।

- **बैंकिंग सेवाओं तक व्यापक पहुँच**

यह प्रयास सभी को बैंकिंग सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिशचित करने में अत्यंत ही सहायक होगा। ऐसा इसलिये क्योंकि इस व्यवस्था में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार हेतु बुनियादी ढाँचा खड़ा करने के बजाय बस एक डिजिटल स्ट्रक्चर की जरूरत होगी।

- **लागत में कमी**

बैंकिंग सेवा प्रदान करने हेतु किसी स्थान विशेष पर पहुँचने की शर्त खत्म हो जाएगी, इससे ट्रांजेक्शनल (लेन–देन सम्बंधी) मूल्य के साथ–साथ ट्रांसपोर्ट खर्च में भी कमी आएगी।

कैशलेस लेन–देन बढ़ेगा तो रिजर्व बैंक को कम नोट छापने होंगे जिससे नोटों की छपाई पर आने वाली भारी लागत को कम किया जा सकता है।

साथ ही एटीएम को सुचारू रूप से चालू रखने में बैंकों का होने वाला खर्च भी कम होगा।

- **जनहितकारी योजनाओं की दक्षता में वृद्धि**

जनता के कल्याण हेतु चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों की दक्षता बढ़ेगी, क्योंकि धन बिचौलियों के हाथ में जाने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंचेगा।

- **तीव्र और समय पर सुपुर्दगी**

नकद भुगतान की तुलना में कैशलेस लेनदेन तीव्र और समय पर प्राप्त एवं भुगतान किये जाते हैं।

- **बेहतर सुरक्षा**

नकद लेनदेन में आपराधिक गतिविधियां अधिक होती हैं, नकद लेन–देन की तुलना में इससे हमें बेहतर सुरक्षा प्राप्त होगी।

कैशलेस (डिजिटल) अर्थव्यवस्था की राह में चुनौतियां एवं बाधाऐं

- **अधिकांश जनसंख्या बैंकिंग गतिविधियों के बाहर**

वर्ष 2015–16 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार बचत कार्यों के सम्बंध में पूरे देश में बैंकिंग गतिविधियों तक मात्र 46 प्रतिशत लोगों की पहुँच है।

जन–धन योजना लागू होने के पश्चात बड़ी संख्या में बैंक अकाउंट तो खुल गए लेकिन अधिकांश खातों से कोई लेन–देन नही हो रहा। कैशलेस अर्थव्यवस्था के निर्माण हेतु यह आवश्यक है कि इन खातों को क्रियाशील बनाया जाए अर्थात् इनसे कुछ लेन–देन हो।

- **असंगठित क्षैत्र का प्रभाव**

यदि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बैंकिंग गतिविधियों के दायरे में आ भी जाए तो कैशलेस होने की मुहिम शायद ही सफल हों, क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी असंगठित क्षैत्र (Informal Sector) में कार्य करने को अभिशप्त है। यहाँ होने वाला अधिकांश लेन–देन नकदी में ही किया जाता है। ऐसे में किसी से यह उम्मीद करना कि वह नकदी में प्राप्त वेतन को अपने बैंक अकाउंट में जमा कर फिर कार्ड या मोबाइल वॉलेट का प्रयोग करेगा तो यह बेईमानी होगी।

- **साइबर सुरक्षा का मुद्दा**

विदित हो कि अक्टूबर 2016 में 30 लाख से अधिक डेबिट कार्डों का विवरण चोरी हो गया था और यह हमारी कमजोर साइबर सुरक्षा का एक उदाहरण हैं। आज देशों के बीच साइबर युद्ध चल रहा है और भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव है। ऐसे में यदि भारत की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था कैशलेस हो जाती है तो हमें अपनी साइबर सुरक्षा को भी मजबूत बनाना होगा।

- **नेटवर्क कनेक्टिविटी और इंटरनेट की लागत**

ग्रामीण क्षैत्रों में इंटरनेट कनेक्शन की अनुपलब्धता या विफलता भारत में आम बात है। इसके अलावा इंटरनेट की लागत अब भी काफी अधिक है।

लोगों में कम्प्यूटर साक्षरता अभी भी कम है। इसके अलावा लोग लेन–देन के लिये इलेक्ट्रॉनिक पद्धति का उपयोग करने के लिये आशंकित हैं।

- **लेन–देन प्रभार**

लेन–देन प्रभार, वार्षिक शुल्क अथवा सुविधा शुल्क का भुगतान कार्ड रखने हेतु किया जाता है जो कि अधिक कार्ड रखने और कार्ड भुगतानों के अधिक उपयोग में बाधा उत्पन्न करता है तथापि यह देखते हुए कि डिजिटल लेन–देन के द्वारा किसी भी समय और कहीं भी भुगतान किया जा सकता है। लेन देन करने वाले डिजिटल लेन–देन से प्राप्त होने वाले लाभों के लिए डिजिटल लेन–देन का विकल्प चुनते हैं।

- **निजता**

नकदी रहित लेन–देन में सदा कोई मध्यस्थ अथवा तीसरा पक्ष शामिल रहता है, जिससे निजता, व्यक्तिगत लेन–देन और रिकॉर्ड अन्य तक पहुँचने का खतरा उत्पन्न होता है, तथापि डिजिटल लेन–देन में संभावित खतरे का संज्ञान लेते हुए संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा अथवा सूचना, जिसमें बैंक खाता अथवा क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा अन्य भुगतान साधनों के ब्यौरों की निजता की सुरक्षा के लिए (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत) सूचना प्रौद्योगिकी (रीजनेबल सिक्यूरिटी प्रैक्टिसेज एवं प्रोसिजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इन्फार्मेशन) नियम, 2011 बनाए गए हैं।

निम्न आरेख (डायग्राम) की मदद से कैशलेस भारतीय व्यवस्था और डिजिटलाइजेशन के विस्तार को समझने का प्रयास करेंगे।

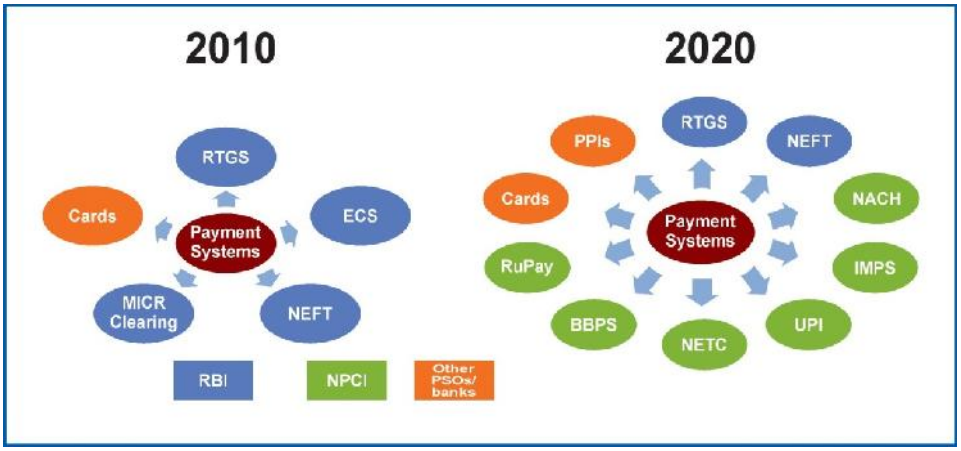

Table 1: India's payment systems

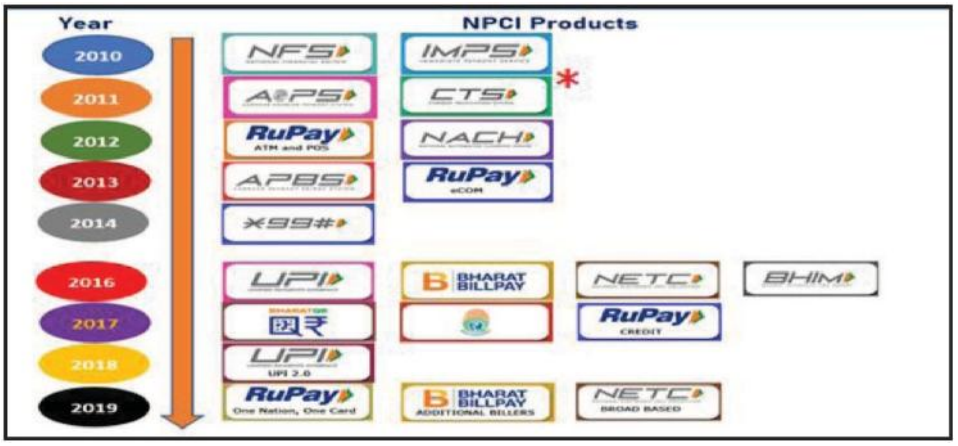

Table 2: Progress made by NPCI in the retail digital payments space

Note - *CTS operations were handed over to NPCI in 2013

Source: RBI Data

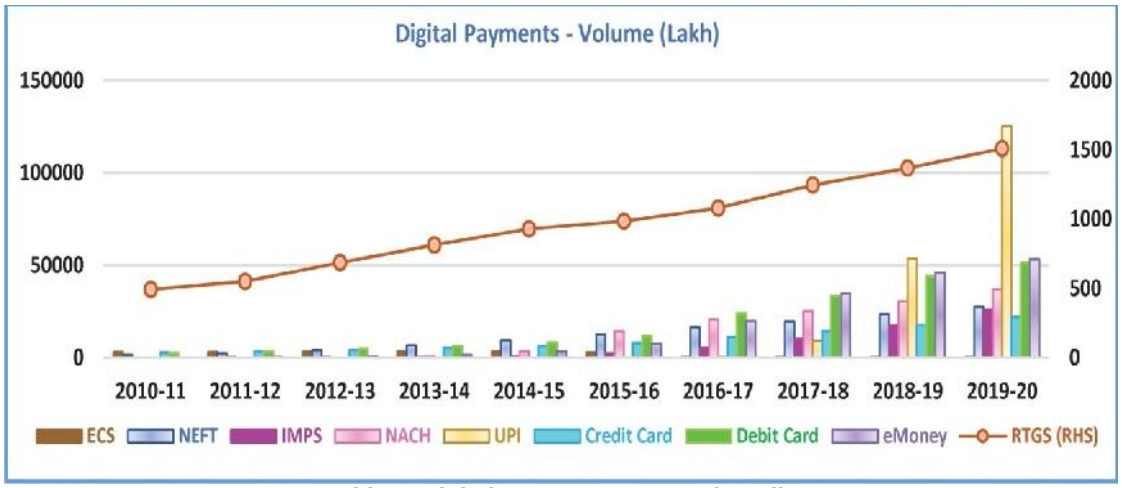

Table 3: Digital Payment Systems in India

Source: RBI Data

2015-16 और 2016-17 में डिजिटल भुगतान
(एनपीसीआई के अनुसार)

संचालन एजेंसी	2015-16		2016-17		वार्षिक वृद्धि %	
	मात्रा (मिलियन में)	मूल्य (बिलियन रुपये में)	मात्रा (मिलियन में)	मूल्य (बिलियन रुपये में)	मात्रा	मूल्य
आरबीआई	1252.88	83273.11	1622.10	120039.68	29.47	44.15
एनपीसीआई	1743.91	5388.74	3175.96	11773.49	82.12	118.48
एम-वॉलेट	603.98	205.84	1322.52	459.30	118.97	123.13
आईसीएस	1923.62	3945.39	3053.38	5953.33	58.73	50.89
कुल	5524.39	92813.08	9173.96	138225.80	66.06	48.93

2015–16 और 2016–17 में डिजिटल भुगतान (एनपीसीआई के अनुसार)

Appendix 1

Payment System Data-2010, 2015 and 2020

Item	Volume (Lakh)			Value (: '000Crore)		
	2010-11	2015-16	2019-20	2010-11	2015-16	2019-20
Payment Systems						
1. Large Value Credit Transfers – RTGS	493	983	1507	48487	82457	131156
Retail Segment						
2. Credit & Debit Transfers	4064	31415	215619	1194	9140	29398
2.1 NEFT	1323	12529	27445	939	8327	22946
2.2 IMPS		2208	25792		162	2338
2.3 UPI			125186			2132
2.4 NACH		14041	36979		380	1976
2.5 ECS	2741	2638	19	255	271	5
2.6 Others			198			1
3. Card Payments	5022	19593	73013	114	399	1535
3.1 Credit Cards	2652	7857	21773	75	241	731
3.2 Debit Cards	2371	11736	51240	39	158	804
4. Prepaid Payment Instruments		7480	53317		48	215
5. Paper-based Instruments	13873	10964	10414	10134	8186	7824
Total Retail Payments (2+3+4+5)	22959	69452	352363	11442	17775	38974
Total Payments (1+2+3+4+5)	23452	70435	353870	59930	100233	170130
Total Digital Payments (1+2+3+4)	9579	59472	343456	49795	92046	162305

Appendix 2

S. No.	Acronym	Expansion
1.	AEPs	Aadhaar-enabled Payment System
2.	ATM	Automated Teller Machine
3.	BHIM	Bharat Interface for Money
4.	e-KYC	Electronic-Know Your Customer
5.	IFSC	Indian Financial System Code
6.	IMPS	Immediate Payment Service
7.	NEFT	National Electronic Funds Transfer
8.	NETC	National Electronic Toll Collection
9.	NPCI	National Payments Corporation of India
10	QR	Quick Response
11.	RTGS	Real Time Gross Settlement
12.	UPI	Unified Payments Interface
13.	UIDAI	Unique Identification Authority of India
14.	USSD	Unstructured Supplementary Services Data
15.	VPA	Virtual Payment Address

निष्कर्ष

भारत की सामाजिक–आर्थिक विशेषताओं को देखते हुए, डिजिटल भुगतानों की आर्थिक प्रणाली को प्रोत्साहित करना चुनौतीपूर्ण कार्य है और यह ई–भुगतानों, सुदृढ़ ऑनलाईन बैंकिंग तंत्रों, नकदी रहित लेन–देन को प्रोत्साहित करने और देशव्यापी डिजिटल लेन–देन तंत्र के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप की आवश्यकता को दर्शाता है। विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल भुगतान में हुई वृद्धि को वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सभी हितधारकों के पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। जैसे–जैसे अवसरों में वृद्धि होती है, वैसे ही चुनौतियां भी बढ़ती हैं। सामने वास्तविक और कई जटिल अवरोध हैं जिनका समाधान किया जाना है ताकि भारत को एक नकदी रहित समाज के रूप में परिवर्तित किया जा सके। भुगतान परिदृश्य की नई कम्पनियों द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने के लिए विनियामक ढांचों को संशोधित और अद्यतन बनाया जा रहा है। ऐसे में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचाए जा सकने वाली डिजिटल संरचना के विकास और प्रदाताओं के बीच अंतर–संचालनात्मकता और प्रतिस्पर्धा तथा नागरिकों के बीच वित्तीय क्षमता भी सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षैत्र के साथ सहयोग कर सकती हैं। यद्यपि पूर्णतया नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने में समय लगेगा, तथापि क्रमिक कदम लोगों का विश्वास जीत सकते हैं और मध्यम अवधि में भारत को एक कम नकदी का प्रयोग करने वाले समाज में परिवर्तित कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Website- cashlessindia.gov.in , niti.gov.in
2. लोक सभा सचिवालय, शोध और सूचना प्रभाग, दिसम्बर 2017
3. RBI, Payment and Sattlement Systems in India, Booklet 2010-20
4. राजस्थान सुजस, सूचना जनसम्पर्क विभाग, जयपुर (सितम्बर–अक्टूबर 2020, नवम्बर–दिसम्बर 2021)
5. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की प्रकाशित रिपोर्ट 2020 व 2021
6. The World Bank, RBI, SBI, की 2020 व 2021 की वार्षिक रिपोर्ट।
7. TFIPOST.in
8. Pooja Maurya Research Fellow, Aligarh Muslim University, Aligarh
9. News Channel, BBC, Aaj Tak, News Nation, Zee Buisness etc.
10. योजना फरवरी 2017, दृष्टि The Vision,
11. मार्च 2020 से दिसम्बर 2021 तक दैनिक भास्कर, पत्रिका, Financial Express, Times of India आदि से सम्बन्धित विशेष लेख, टिप्पणीयाँ एवं सम्पादकीय से एकत्रित की गई सामग्री।

❖◆❖